



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४९ पटना, बुधवार, १५ अग्रहायण १९३९ (श०)  
६ दिसम्बर २०१७ (ई०)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-4	भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-१-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०ए०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-९—विज्ञापन ---
भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---	भाग-९-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 5-5
भाग-४—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क 6-9

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

### खान एवं भूतत्व विभाग

#### अधिसूचना

14 नवम्बर 2017

सं० 2/एम०एम०(बा०)—04/13-7024/एम०—श्री के०के० पाठक, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार स्टेट मार्टिंग कॅरपोरेशन लिमिटेड, पटना का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
अरुण प्रकाश, विशेष सचिव।

### निगरानी विभाग

#### सूचना भवन, पटना

#### अधिसूचना

27 नवम्बर 2017

सं० नि० वि० स्था०—139/2013-4868—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—2804 दिनांक 29.03.2010 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या—5448 दिनांक 05.11.2014 द्वारा सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षकों को अनुबंध के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया था, जिनका विभागीय अधिसूचना संख्या—821 दिनांक 10.03.2016 द्वारा एक वर्ष की अवधि विस्तार किया गया था। पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या—4518 दिनांक 30.11.2016 द्वारा एक वर्ष अर्थात् दिनांक 14.11.2017 तक के लिए अवधि विस्तार किया गया था।

उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका—2(ख) के उप कंडिका—(v) में अंकित प्रावधान के आलोक में निम्नांकित पुलिस उपाधीक्षकों को उनके नाम के सामने कॉलम—6 में अंकित एक वर्ष की अवधि/65 वर्ष तक (जो पहले हो) के लिए सेवा का अवधि विस्तार किया जाता है :-

क्रमांक	नाम/पदनाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि	योगदान की तिथि	सेवा विस्तार की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	श्री विनय कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक	02.01.1954	31.01.2014	14.11.2014	15.11.2017 से 14.11.2018 तक
2	श्री तारणी प्रसाद यादव पुलिस उपाधीक्षक	07.07.1953	31.07.2013	14.11.2014	15.11.2017 से 06.07.2018 तक  (65 वर्ष की आयु पूरा होने के फलस्वरूप)

2. नियोजन संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या—5448 दिनांक 05.11.2014 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

3. इसमें राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

**परिवहन विभाग**

**अधिसूचना**

**27 नवम्बर 2017**

सं० 05/स्था०(डी०टी०ओ०)-30/2013-5962/परि०—परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-3095 दिनांक 13.06.2017 द्वारा श्री ब्रजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा को रजौली चेकपोस्ट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

2. श्री ब्रजेश कुमार के स्थान पर श्री अखिलेश कुमार (बि०प्र०से०), भूमि सुधार, उप समाहर्ता, रजौली को अपने कार्यों के अतिरिक्त करारोपण पदाधिकारी के रूप में रजौली चेकपोस्ट पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
विनय कुमार राय, उप—सचिव।

**Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya**

**Office Order**

*The 24<sup>th</sup> November 2017*

No. I- स्था०-71/2017-4294—In the light of proposal received from Collector, Gaya (letter no. 797/सा०द. 30/10/2017.) Power of certificate officer have been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914

Sl.	Name of Officer	Designation	Remarks
1	Sri Ashok Kumar Singh	Circle Officer, Khizarsarai	Circle Office, Khizarsarai
2	Sri Shiv Shankar Roy	Circle Officer, Bodhgaya	Circle Office, Bodhgaya
3	Smt. Anita Bharti	Circle Officer, Tekari	Circle Office, Tekari
		Circle Officer, Konch	Circle Office, Konch
4	Sri Ram Pravesh Ram	Circle Officer, Paraiya	Circle Office, Paraiya
5	Sri Ravi Shankar	Circle Officer, Mohanpur	Circle Office, Mohanpur
6	Sri Jitendra Kumar Pandey	Circle Officer, Manpur	Circle Office, Manpur
		Circle Officer, Wazirganj	Circle Office, Wazirganj
7	Sri Balbant Kumar Pandey	B.D.O., Guruya	Circle Office, Guruya

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 15/11/2017

By Order,  
Sd/-Illegible,  
Secretary to Commissioner.

*The 3<sup>rd</sup> November 2017*

No. XI-L रा०-31/2017-3959—In the light of proposal received from Collector, Nawadah (letter no. 422dt. 23/08/2017.) power of certificate officer has been delegated to Sri Birendra Kumar, Deputy Collector Land Reforms, Nawadah for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 25/10/2017

By Order,  
Sd/-Illegible,  
Secretary to Commissioner.

*The 22<sup>nd</sup> November 2017*

No. XI-L रा०-46/2017-4268—In the light of proposal received from Collector, Aurangabad (letter no. 1414dt. 23/10/2017.) power of certificate officer have been delegated to

following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914 **for four months only.**

Sl.	Name of Officer	Designation	Remarks
1	Sri Anil Kumar	Circle Officer, Kutumba	For Kutumba & Aurangabad Circle
2	Sri Awadhesh Kumar Nepali	Circle Officer, Goh	For Goh Circle

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 03/11/2017

By Order,  
Sd/-Illegible,  
*Secretary to Commissioner.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण  
सूचनाएं इत्यादि

### सूचना

सं० 1518—मैं शुभाशीष पता आई. डी. एच. कॉलोनी एन०एम०सी०एच० पटना। शपथ-पत्र संख्या 5208 दिनांक  
18/05/2017 से शुभाशीष कश्यप के नाम से जाना जाऊंगा।

शुभाशीष।

No. 1518—I SHUBHASHISH Add-I.D.H. Colony N.M.C.H. Patna Affidavit No.-5208  
date 18/05/2017 onward I shall be known as SHUBHASHISH KASHYAP.

SHUBHASHISH.

No. 1530—I Bhaiya Ram Singh, S/o Sukhu Singh Vill-Tekanpura, PO-Kusumahara, PS-  
Surypura, Dist-Rohtas declare vide aff. No. 4846 dated 25.11.17 Bhai Ram Singh alias Bhaiya  
Ram Singh both name is mine.

Bhaiya Ram Singh.

No. 1531—I Sury Mano Devi W/o Bhaiya Ram Singh, Vill-Tekanpura, PO-Kusumahara,  
PS-Surypura, Dist-Rohtas declare vide aff. No. 4845 dated 25.11.17 Sury Mano Devi alias Suraj  
Mano Devi both name is mine.

Sury Mano Devi.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 38—571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)—01—01/2015—6713  
 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
 गृह विभाग (कारा)

संकल्प

27 नवम्बर 2017

श्री राकेश कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, उपकारा, रोसड़ा (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान) के विरुद्ध उनके उपकारा, रोसड़ा में पदस्थापन काल में विपत्र संख्या—113/11—12 से संबंधित सभी 09 अभिश्रवों का विधिवत् संधारण नहीं करने एवं सरकारी राशि का नियमानुकूल व्यय नहीं किये जाने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6184 दिनांक 05.10.2016 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त विभागीय जाँच आयुक्त, मुँगेर प्रमंडल, मुँगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. आयुक्त कार्यालय, मुँगेर प्रमंडल, मुँगेर के पत्रांक 840 दिनांक 28.02.2017 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच—सह—संचालन पदाधिकारी, मुँगेर प्रमंडल, मुँगेर के जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक 1378 दिनांक 24.03.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री कुमार के द्वारा अपने पत्रांक 476/जेल दिनांक 31.03.2017 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि सभी अभिश्रव उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं विधिवत् संधारित है तथा जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा जांचोपरान्त ही भुगतान किया गया है। उनका कहना है कि उक्त अवधि में उपकारा, रोसड़ा में कोई भी लिपिक, लेखापाल, सहायक अधीक्षक या लेखा का ज्ञान रखने वाला कारा कर्मी पदस्थापित नहीं था। जिस कारण अभाववश सभी अभिश्रव उनके ही द्वारा पारित किये गये जिसे करना अनिवार्य था। श्री कुमार का कहना है कि उपकारा, रोसड़ा में अधीक्षक आवास था ही नहीं, उपाधीक्षक आवास में कमियों को दूर कर किसी तरह वे निवास कर रहे थे। उनके द्वारा कार्यरत काराधीक्षक आवास के प्राक्कलन हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण भवन, समस्तीपुर से प्राथमिकता के आधार पर प्राक्कलन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। साथ ही जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के

ज्ञापांक 3287 दिनांक 17.06.2013 का प्रसंग देते हुए भी कार्यपालक अभियन्ता से आग्रह किया गया था। कारा परिसर की घेराबंदी हेतु पत्रांक 405 दिनांक 14.09.2009 द्वारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना से भी उचित आदेश पारित करने का आग्रह किया गया था। इसके बावजूद जब कार्रवाई संभव नहीं हो सकी तो कारा के सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से बचाने, फैली कुव्यवस्था को दूर करने तथा अतिसंवेदनशील कारा की सुरक्षा व्यवस्था एवं संसीमित बंदियों के हित में अधीक्षक स्तर से नियमतः कार्रवाई करते हुए साफ-सफाई तथा जर्जर मकानों की रंग-रोगन युद्धस्तर पर कराकर सम्पूर्ण कारा को सुधार गृह के अनुरूप साफ-सफाई कराया गया था। उक्त राशि का व्यय व्यावसायिक मद से किया गया। उपरोक्त सभी व्यय से संबंधित विवरणी के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल अंकेक्षण प्रतिवेदन नहीं है।

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाब की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार इसमें सभी नौ (09) अभिश्रवों को विधिवत् संधारित नहीं होना, अभिश्रव पर सहायक लेखापाल के जांचोपरान्त उनका हस्ताक्षर नहीं होना आदि त्रुटि पाया गया। जिला पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है। श्री कुमार का यह कथन कि अभिश्रवों की जांच करने वाला कोई कर्मी पदस्थापित नहीं था, गलत है क्योंकि उस समय उक्त कार्य को सम्पादित करने योग्य 04 (चार) कर्मी वहाँ पदस्थापित थे। अधीक्षक आवास के रंग-रोगन, घेराबन्दी एवं जंगल-झाड़ की साफ-सफाई पर 29,000/- (उन्तीस हजार) रुपये का व्यय आरोपित पदाधिकारी द्वारा किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। सरकारी भवनों का रख-रखाव भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है न कि कारा को उपलब्ध कराये गये किसी आवंटन से। इसी तरह कारा के शौचालय टंकी की साफ-सफाई, बिजली-बत्ती एवं जंगल-झाड़ की कटाई/सफाई के लिए कुल 93,200/- (तिरानवे हजार दो सौ) रुपये का व्यय किया गया है। उक्त राशि का व्यय किस मद से किया गया है स्पष्ट नहीं है। जिला पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में भी इसपर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी आरोप प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री कुमार का जबाब स्वीकार्य नहीं है।

5. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया :-

**“ तीन (03) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड ”।**

6. उपर्युक्त विनिश्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 3406 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1933 दिनांक 06.11.2017 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, उपकारा, रोसड़ा (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

**“ तीन (03) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड ”।**

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

कृषि विभाग

आदेश

3 नवम्बर 2017

सं० 2 (गो०) सी०-2-87/2016 1041/कृ०—स्व० सुधीर कुमार वाजपेयी, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति उप निदेशक (शष्य), बीज विश्लेषण, बिहार (मृत) के विरुद्ध विभिन्न गम्भीर आरोपों के लिए कृषि निदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक 2169 दिनांक 19.5.2016 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया।

स्व० वाजपेयी के सरकारी सेवावधि में दिनांक 20.05.2017 को आकस्मिक निधन हो जाने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा सामान्य प्रशासन के पत्रांक 8811 दिनांक 18.07.2017 में नहिित प्रावधानों के आलोक में स्व० वाजपेयी को आरोप से मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में स्व० सुधीर कुमार वाजपेयी, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति उप निदेशक (शष्य), बीज विश्लेषक, बिहार (सम्प्रति मृत) को आरोप से मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,  
वीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव।

**VIGILANCE DEPARTMENT  
BIHAR, PATNA  
FORM No. I**

**DECLARATION**

*The 7<sup>th</sup> November 2017*

**(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)**

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**07/2016-4515**—WHEREAS, It is alleged that **Sri Lalan Prasad Singh, S/o Late Shyam Singh, the then In-charge Executive Engineer, Patna Municipal Corporation, Patna. Permanent Address : Vill. - Hathiya, P.S. + Dist. - Sheikhpura at present Gandhi Nagar, infront of Patliputra Station, P.S. - Rajiv Nagar, Distt. - Patna**, while holding the post of **Sri Lalan Prasad Singh, the then In-charge Executive Engineer, Patna Municipal Corporation, Patna** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence of under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. **Case No. 94/2014 dated 02.12.2014.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of **Sri Lalan Prasad Singh, S/o Late Shyam Singh, the then In-charge Executive Engineer, Patna Municipal Corporation, Patna**, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;



NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,

Sd./-Illegible, *Principal Secretary*.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>